भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3303

(जिसका उत्तर सोमवार दिनांक **16** दिसम्बर**, 2024/25** अग्रहायण**, 1946 (**शक) को दिया जाना है)

एफएमसीजी की शहरी मांग में गिरावट

3303. सुश्री सयानी घोषः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी) की शहरी मांग में गिरावट आई है, जिसके कारण क्षेत्र की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही में 10.1% से घटकर वित्त वर्ष 2025 (एक वर्ष में) की पहली तिमाही में केवल 2.8% रह गई है और यदि हां, तो खपत को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या शहरी मांग में कमी का कारण खाद्य मुद्रास्फीति सहित उच्च मुद्रास्फीति, वास्तविक मजदूरी की स्थिर वृद्धि और उच्च ब्याज दरें हैं, जैसा कि विशेषज्ञों ने बताया है और यदि हां, तो सुधार के लिए हाल ही में लिए गए नीतिगत निर्णयों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने विभिन्न एफएमसीजी प्रमुखों के बयानों पर ध्यान दिया है कि यह लुप्त हो रहे 'मध्यम वर्ग सिंड्रोम' का परिणाम है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): निजी एजेंसियों द्वारा खपत, निवेश और अन्य इकोनॉमिक वेरिएबल के संबंध में प्रकाशित कई उच्च आवृत्ति संकेतक हैं। सरकार ऐसी जानकारी पर ध्यान देती है। हालांकि, सकल घरेलू उत्पाद के घटकों के बारे में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा दी गई समेकित जानकारी के अनुसार, स्थिर कीमतों पर निजी अंतिम खपत व्यय में 2024-25 की पहली तिमाही में 7.4 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की गई, जबकि 2023-24 की पहली तिमाही में यह 5.5 प्रतिशत थी। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स के संबंध में कोई अलग जानकारी नहीं देती है।

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि वर्तमान साप्ताहिक स्थिति में प्रति व्यक्ति औसत मजदूरी/वेतन आय में वृद्धि 2023-24 की खुदरा मुद्रास्फीति दर से अधिक है। जबकि नीतिगत रेपो दर फरवरी 2023 से अपरिवर्तित बनी हुई है, खुदरा मुद्रास्फीति दर 2024-25 (अप्रैल-अक्टूबर) में घटकर 4.8% हो गई, जबकि 2023-24 में यह 5.4% थी।

कौशल, रोजगार सृजन, मुफ्त खाद्यान्न की लक्षित व्यवस्था और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उपायों पर सरकार द्वारा ध्यान केंद्रित कर पाने से घरेलू आय और खपत में सुधार होने की संभावना है।

(ग) गैर-सरकारी स्रोत इकोनॉमिक वेरिएबल में रुझानों का अपना आकलन करते हैं। तथापि, सरकार के पास 'मध्यम वर्ग सिंड्रोम' के लुप्त होने के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

****